

[2023] 4 एस. सी. आर 18

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

क.

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम

नवीन मैथ्यू फिलिप और ए. एन. आर. ईटीसी। ईटीसी। (2023 की सिविल अपील संख्या 2861-62)

अप्रैल 17, 2023

[संजीव खन्ना और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002:

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-ऋणकर्ताओं द्वारा बकाया राशि के भुगतान में चूक से संबंधित मामला-यू/एस के तहत नोटिस जारी करना। 13(4) - उच्च न्यायालय के समक्ष नोटिसों को चुनौती देने वाले उधारकर्ताओं द्वारा लिखित याचिकाएं-ऋण वसूली न्यायाधिकरण उस समय कार्यात्मक नहीं था जब कहा गया था कि रिट याचिकाएं दायर की गई थीं-हालांकि, मार्च 2022 के महीने से ऐसा हो गया-इस बीच, एक एसएलपी में, इस न्यायालय द्वारा लंबित मामलों को संबंधित न्यायाधिकरणों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया जब वे अपने संबंधित पीठासीन अधिकारियों के साथ विधिवत प्रभारी के रूप में काम करना शुरू करते हैं-उक्त आदेश के बावजूद, उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकाओं पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी ली और उधारकर्ता को 12 महीने में स्थगित भुगतान करने की अनुमति दी-इस न्यायालय के समक्ष अपील-अपीलकर्ता का मामला कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत को कानून की पुनरावृत्ति के लिए दबाव डालते हुए बाधित नहीं किया जा सकता है जो भविष्य में ऐसी रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करने में उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन कर सकता है। अपीलार्थी के निष्पक्ष रुख को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत को बाधित नहीं किया जाना चाहिए-अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियां अपेक्षाकृत व्यापक हैं, लेकिन उनका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में करने की आवश्यकता है-ऐसे मामलों में जहां विधायिका ने उचित निवारण के लिए एक विशिष्ट तंत्र प्रदान किया है, संवैधानिक उपाय का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए-भारत का संविधान-अनुच्छेद 226।

ग

डी.

ई.

च

सरफेसी अधिनियम-उद्देश्य और उद्देश्य-चर्चा की गई। लिखें:

जी.

प्रमाणपत्र का लेखन-जारी करना, कब-आयोजित: किसी निर्णय पर जारी किया जाना है जब न्यायालय को पता चलता है कि प्रक्रिया कानून या कानून के अनुरूप नहीं है-सभी उल्लंघनों को दूर करने के लिए रिट जारी नहीं किया जाना है-रिट अदालत निर्णय के साथ खुद को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है-ए

एच.

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन मैथ्यू फिलिप और ए. एन. आर. ईटीसी। ईटीसी।

प्रक्रिया में दोष ढूंढते समय प्राधिकरण बनाना-जब एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, तो उससे वैधानिक उल्लंघन सहित तथ्य और कानून के मुद्दों का निर्धारण करने की उम्मीद की जाती है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 226।

मैंडमस जारी करने की मांग करने वाले निजी व्यक्ति के खिलाफ वाणिज्यिक मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष मैंडमस-जारी करने-रिट याचिका का रिट-आयोजित:मैंडमस का रिट एक विशेषाधिकार प्राप्त रिट है-किसी भी कानूनी अधिकार के अभाव में, न्यायालय उक्त शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है-वित्तीय लेनदेन में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब एक पक्ष अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आता है।

ग

न्यायिक अवहेलना:सर्फेसी अधिनियम से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालयों का हस्तक्षेप-आयोजित:उक्त प्रथा की निंदा की जाती है-उच्च न्यायालयों से ऐसे मामलों पर विचार न करने का अनुरोध-जब कोई कानून किसी विशेष तरीके को निर्धारित करता है, तो दरकिनार करने के प्रयास को रिट अदालत द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा-एक वादी न्यायाधिकरण से संपर्क करने के गैर-अनुपालन से बच नहीं सकता है जिसके लिए शुल्क के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है और एक विकल्प के रूप में संवैधानिक उपाय का उपयोग करता है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 226।

डी.

न्यायिक सूचना:वाणिज्यिक मामले, जहां एक कानून के माध्यम से एक प्रभावी और प्रभावी वैकल्पिक मंच का गठन किया गया है-ऐसे मामलों में अनुच्छेद 226 का आह्वान करते हुए कुछ उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, जिससे इस न्यायालय के समक्ष मामलों की नियमित आपूर्ति होती है-इस न्यायालय द्वारा लिया गया न्यायिक नोटिस।

ई.

हरि विष्णु कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक **(1955) 1 एससीआर 1104**; मार्लिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ,

च

(2004) 4 एससीसी 311:[2004] 3 एस. सी. आर. 982-पर निर्भर था।

राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ एच. पी. **(2021) 6 एस. सी. सी. 771**; फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्व भारती विद्या मंदिर और अन्य। **(2022) 5 एस. सी. सी. 345**; फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस और ओआरएस। **(2003) 10 एससीसी 733**:

जी.

[2003] 4 पूरक।एस. सी. आर. 121; भारतीय स्टेट बैंक बनाम.

अरविंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड **2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1522**; यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और

अन्य **(2010) 8 एस. सी. सी. 110:[2010] 9 एससीआर 1**; अधिकृत

अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और एक अन्य बनाम।

एच.

20 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट **[2023] 4 एस. सी. आर.**

क.

मैथ्यू के. सी. (2018) 3 एससीसी 85:[2018] 1 एससीआर 233;

वरिमडुगु ओबीआई रेड्डी बनाम बी. श्रीनिवासुलु और अन्य

(2023) 2 एस. सी. सी. 168-संदर्भित। निर्णीत विधि संदर्भ

(2022) 5 एस. सी. सी. 345

संदर्भित किया गया है

पैरा **11,17**

[2003] 4 पूरक।एस. सी. आर. 121 पैरा 11,17 [2010] 9 एस. सी. आर. 1 को संदर्भित करता है।

संदर्भित किया गया है

पैरा **11,17**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11,17**

[2018] 1 एससीआर 233

(2023) 2 एससीसी 168

संदर्भित किया गया है

पैरा **11,17**

ग

[1955] 1 एससीआर 1104

पर भरोसा किया

पैरा **14**

[2004] 3 एससीआर 982

पर भरोसा किया

पैरा **15**

(2021) 6 एस. सी. सी. 771

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 2861-2862।

डी.

एनर्कुलम में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.10.2022 से डब्ल्यू. ए. संख्या 1492 और 2022 के 1497 में।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. कार्तिक, अर्श खान, सुश्री स्मृति सुरेश, सुश्री श्रीप्रिया के, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

ई.

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के जॉय, अब्राहम सी. मैथ्यू, आलिम अनवर, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

च

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. निजी वित्तीय लेन-देन से संबंधित एकतरफा प्रस्ताव को लागू करने की मांग करते हुए, एकमुश्त निपटान का पालन करने में विफलता पर बकाया की वसूली के लिए उठाए गए कदमों पर सवाल उठाते हुए, उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने की मांग की गई।अपीलार्थियों द्वारा की गई कार्रवाई में विधिवत हस्तक्षेप करके किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, केरल उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए गए, जो वर्तमान अपीलों में विवादित हैं।

जी.

एच.

21

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनामनवीन

मैथ्यू फिलिप और एएनआर। ईटीसी। ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

क.

3. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन और प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुना।

4. उत्तरदाताओं द्वारा दो ऋण प्राप्त किए गए थे, एक आवास/केसीसी ओवरड्राफ्ट ऋण और एक व्यावसायिक ऋण।उत्तरदाताओं के खातों को 27.05.2021 पर गैर-निष्पादित संपत्ति ("NPA") के रूप में घोषित किया गया था।वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के तहत नोटिस क्रमशः 07.08.2021 और 12.08.2021 पर जारी किए गए थे, जिनका उत्तर प्रत्यर्थियों द्वारा 28.10.2021 पर दिया गया था, जिसमें ऋण चुकाने के लिए बारह महीने का समय मांगा गया था।

ग

5. आश्चर्यजनक रूप से, दिनांकित 28.10.2021 के जवाब के 3 दिनों के भीतर, निर्धारित वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले, 2021 की रिट याचिका संख्या 23940 दाखिल करके, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारी किए गए मांग नोटिस को चुनौती दी गई थी।उक्त सूची का मनोरंजन करते हुए, अपीलार्थियों को प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश जारी किया गया था।उपरोक्त आदेश के उचित अनुपालन में, प्रत्यर्थियों को बारह के बजाय पांच किशतों में उपार्जित बकाया जमा करने की अनुमति दी गई थी।प्रदत्त विस्तारित लाभ का उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग नहीं किया गया था, और इसलिए, एक अनुस्मारक भी भेजा गया था।कोई जवाब नहीं मिलने पर, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत दो नोटिस 02.12.2021 और 20.12.2021 पर जारी किए गए।

डी.

ई.

6. उपरोक्त नोटिसों को चुनौती देते हुए, उत्तरदाताओं द्वारा दो रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें 2021 की रिट याचिका संख्या 30238 और 2021 की 30450 शामिल हैं, जो एकतरफा प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए एक सकारात्मक निर्देश के लिए प्रार्थना करते हुए प्रमाण पत्र की एक रिट के माध्यम से की गई कार्रवाई पर सवाल उठाती हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हालांकि उपरोक्त रिट याचिकाएं दायर करने के समय कार्यात्मक नहीं था, लेकिन मार्च, 2022 के महीने से ऐसा हो गया।

च

7. विभिन्न न्यायाधिकरणों में उचित निर्णय के लिए पीठासीन अधिकारी का पद खाली होने के परिणामस्वरूप तत्कालीन मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 10911 दिनांक 16.12.2021 में एक आदेश पारित किया गया था।

जी.

“याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. में सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण पक्षों को हो रही कठिनाई को हमारे संज्ञान में लाया है।

एच.

22

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

उन्होंने अनुरोध किया कि डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. के समक्ष मामलों पर राज्य के भीतर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और औद्योगिक न्यायाधिकरण जैसे अन्य न्यायाधिकरणों द्वारा विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है।

पक्षकारों द्वारा सामना की जा रही समस्या को हल करने के लिए, कुछ समय के लिए और विशुद्ध रूप से एक विराम-अंतराल व्यवस्था के रूप में, हम संबंधित उच्च न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वे अगले आदेश तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर विचार करें।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि एक बार न्यायाधिकरणों का गठन हो जाने के बाद, मामलों को उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायाधिकरणों को भेजा जा सकता है। मामले को 21-1-2022 पर सूचीबद्ध करें।”

ग

8. जैसा कि देखा जा सकता है, आदेश स्व-व्याख्यात्मक है, यह स्पष्ट करता है कि यह केवल एक अंतरिम व्यवस्था है, और इसलिए, लंबित मामलों को संबंधित न्यायाधिकरणों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए जब वे अपने संबंधित पीठासीन अधिकारियों के साथ कार्य करना शुरू कर दें। उपरोक्त मामले का निपटारा दिनांक 12.09.2022, "1 के आदेश द्वारा किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील का कहना है कि चूंकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण में पद भर दिया गया है, इसलिए कारण नहीं बचता है।

डी.

ई.

2. विशेष अनुमति याचिका का तदनुसार निपटारा इस न्यायालय द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त किए बिना किया जाता है। 3. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।”

9. इस न्यायालय द्वारा ऊपर पारित आदेशों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को 20 किशतों में आस्थगित भुगतान करने की अनुमति देकर, योग्यता के आधार पर उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी ली, जो एक राहत थी जिसके लिए अनुरोध किया गया था। 2022 की रिट अपील संख्या 1492 और 2022 की 1497 में विद्वत खंड पीठ द्वारा किशतों को संशोधित कर 12 महीने कर दिया गया था, जैसा कि मूल रूप से उत्तरदाताओं द्वारा अनुरोध किया गया था, जबकि योग्यता के आधार पर विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए ऋणदाता बैंक ने वर्तमान अपील दायर की है।

च

जी.

10. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत को कानून की पुनरावृत्ति के लिए दबाव डालते समय बाधित नहीं किया जा सकता है जो उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन कर सकता है।

एच.

23

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन

मैथ्यू फिलिप और एनआर। ईटीसी। ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

न्यायालय भविष्य में ऐसी रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करेगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अकेले अपीलार्थियों से संबंधित लगभग 185 मामलों में, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के कार्यशील होने के बाद भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बाद 35 रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता स्वयं सरफेसी अधिनियम के उद्देश्य को विफल करते हुए चूककर्ता उधारकर्ताओं/गारंटर्स से देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हैं।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के ध्यान में लाया कि वित्तीय लेन-देन पर निजी व्यक्तियों को शामिल करने वाली एक रिट याचिका विचारणीय नहीं है। स्थिति तय होने के बावजूद, विभिन्न उच्च न्यायालयों का हस्तक्षेप जारी है। 2002 के अधिनियम 54 के उद्देश्य को इस तरह के हस्तक्षेप से विफल किया जा रहा है। वैकल्पिक उपचार प्रभावी और प्रभावी होने के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता, या तो प्रमाण पत्र का एक रिट या अनिवार्य होना चाहिए था, लागू नहीं किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार हस्तक्षेप के अपीलार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें निम्नलिखित निर्णयों के माध्यम से ले गए:

ग

डी.

- फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्व भारती विद्या मंदिर और अन्य (2022) 5 एस. सी. सी. 345।

ई.

- फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस और अन्य, (2003) 10 एस. सी. सी. 733।
- भारतीय स्टेट बैंक बनाम अरविंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1522।
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य, (2010) 8 एससीसी 110

च

- अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और एक अन्य बनाम मैथ्यू के. सी., (2018) 3 एससीसी 85
- वरिमडुगु ओबीआई रेड्डी बनाम बी. श्रीनिवासुलु और अन्य, (2023) 2 एससीसी 168।

जी.

12. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि रिट याचिका दायर करने के समय न्यायाधिकरण काम नहीं कर रहा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपलब्ध शक्ति को छीन नहीं लिया जा सकता है, इसके अस्तित्व के बावजूद

एच.

24

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

न्यायाधिकरण। अपीलार्थियों द्वारा लिए गए रुख की सराहना करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब चरम कदम उठाए जाते हैं, तो एक वादी के पास रिट अदालत से संपर्क करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता है।

13. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा लिए गए उचित रुख को देखते हुए, हम पारित किए गए विवादित आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हालाँकि, हम वाणिज्यिक मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करते हुए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर कानून की स्थिर स्थिति को दोहरा सकते हैं, जहाँ एक कानून के माध्यम से एक प्रभावी और प्रभावी वैकल्पिक मंच का गठन किया गया है। हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए भी विवश हैं कि कुछ उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना जारी रखते हैं, जिससे इस न्यायालय के समक्ष मामलों की नियमित आपूर्ति होती है। ऐसा ही एक उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का है।

ग

14. जब न्यायालय को पता चलता है कि प्रक्रिया कानून या कानून के अनुरूप नहीं है, तो किसी निर्णय पर प्रमाणपत्र का एक रिट जारी किया जाना है। दूसरे शब्दों में, अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे निर्धारित कारणों के साथ प्रक्रिया में गलती पाते हुए निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के साथ खुद को प्रतिस्थापित करें। सभी उल्लंघनों को दूर करने के लिए इस तरह की रिट जारी किए जाने की उम्मीद नहीं है। जब एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, तो उससे वैधानिक उल्लंघन सहित तथ्य और कानून के मुद्दों पर गौर करने की उम्मीद की जाती है। यह प्रश्न कि क्या इस तरह का उल्लंघन विवेकाधीन के खिलाफ एक अनिवार्य पर्चे पर होगा, मुख्य रूप से न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। इसी तरह, छूट, सहमति और बहिष्कार को नियंत्रित करने वाला मुद्दा भी। हम हरि विष्णु के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना चाहते हैं।

डी.

ई.

कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक, (1955) 1 एससीआर 1104,

“फिर सवाल यह है कि क्या वर्तमान मामले में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उचित आधार हैं। हमारे सामने प्रमाण पत्र के स्वरूप और दायरे और उन शर्तों के बारे में काफी तर्क था जिनके तहत इसे जारी किया जा सकता था। पैरी एंड कंपनी बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया है।

च

वाणिज्यिक कर्मचारी संघ, मद्रास [(1952) एससीआर 519], वीरप्पा पिल्लई बनाम रमन और रमन लिमिटेड और अन्य [(1952) एससीआर 583], इब्राहिम अबूबकर बनाम कस्टोडियन जनरल

जी.

[(1952) एस. सी. आर. 696] और हाल ही में टी. सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा [(1955) एस. सी. आर. 250] इन प्राधिकरणों पर, निम्नलिखित प्रस्तावों को स्थापित के रूप में लिया जा सकता है: (1) अधिकारिता की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जैसे कि जब कोई निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या ए

एच.

25

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन

मैथ्यू फिलिप और एनआर। ईटीसी। ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

इसका अभ्यास करने में विफल रहता है। (2) प्रमाणपत्र तब भी जारी किया जाएगा जब न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने निस्संदेह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। (3) प्रमाणपत्र की रिट जारी करने वाला न्यायालय एक पर्यवेक्षी के प्रयोग में कार्य करता है न कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र में। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों। यह इस सिद्धांत पर है कि एक न्यायालय जिसे किसी विषय-वस्तु पर अधिकारिता प्राप्त है, उसे गलत और सही दोनों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है, और जब विधानमंडल उस निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो वह अपने उद्देश्य और नीति को विफल कर देगा, यदि कोई उच्चतर न्यायालय साक्ष्य के आधार पर मामले की फिर से सुनवाई करता है, और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रमाणपत्र में प्रतिस्थापित करता है। ये प्रस्ताव अच्छी तरह से तय किए गए हैं और विवाद में नहीं हैं।

ग

(4) आगे जिस प्रश्न पर कुछ विवाद हुआ है, वह यह है कि क्या एक रिट जारी की जा सकती है, जब निचली अदालत या न्यायाधिकरण का निर्णय कानून में गलत है। यह सवाल उठ रहा है

डी.

रेक्स बनाम नॉर्थम्बरलैंड क्षतिपूर्ति अपील में विचार

न्यायाधिकरण; पूर्व पक्षीय शॉ [(1951) 1 के. बी. 711], और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब कोई न्यायाधिकरण "बोलने का आदेश" देता है और निर्णय के समर्थन में उस आदेश में दिए गए कारण कानून की दृष्टि से खराब होते हैं, तो प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। यह लॉर्ड गोडार्ड, सी. जे. द्वारा इंगित किया गया था कि इसे हमेशा के वास्तविक दायरे के रूप में समझा गया था

ई.

शक्ति। वालसाल ओवरसियर बनाम लंदन और उत्तर पश्चिमी राय।

कं. [(1879) 4 ए. सी. 30] और रेक्स बनाम नेट बेल लिबर लिमिटेड। [(1922) 2 ए. सी. 28] को इस दृष्टिकोण के समर्थन में उद्धृत किया गया था। वालसाल में

च

ओवरसियर बनाम लंदन और उत्तर पश्चिमी राय। कं. [(1879) 4 ए. सी.

30] लॉर्ड केन्स, एल. सी. ने निम्नलिखित रूप में देखा: “यदि चतुर्थांश सत्र न्यायालय के आदेश के सामने कुछ भी ऐसा था जिससे पता चलता है कि आदेश गलत था, तो क्वींस बेंच के न्यायालय को आदेश लाने के लिए कहा जा सकता है, और आदेश को देखने के लिए कहा जा सकता है, और इसे उसके चेहरे पर देखने के लिए कहा जा सकता है, और यदि अदालत को इसके चेहरे पर त्रुटि मिलती है, तो इसे रद्द करके इसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए कहा जा सकता है।”

जी.

रेक्स बनाम नैट बेल लिंकर एल. डी. [(1922) 2 ए. सी. 128] लॉर्ड सुमनर ने कहा:

एच.

26

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

“यह पर्यवेक्षण दो बिंदुओं पर जाता है; एक निम्न अधिकार क्षेत्र का क्षेत्र और इसके अभ्यास की योग्यता और शर्तें हैं; दूसरा इसके अभ्यास के दौरान कानून का पालन है।”

रेक्स बनाम नॉर्थम्बरलैंड क्षतिपूर्ति अपील न्यायाधिकरण में निर्णय; एक्स पार्टी शॉ [(1951) 1 के. बी. 711] को लिया गया था।

अपील में, और रेक्स बनाम में अपील न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।

नॉर्थम्बरलैंड क्षतिपूर्ति अपील न्यायाधिकरण; पूर्व पक्षीय

शॉ [(1952) 1 के. बी. 338] यह कहते हुए कि कानून की त्रुटि प्रमाण पत्र देने का आधार थी, विद्वान न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि यह रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट होना चाहिए। डेनिंग, एल. जे. जिन्होंने व्यापक और सामान्य शब्दों में शक्ति का उल्लेख किया, उन्होंने कहा:

ग

“यह देखा गया होगा कि सभी मामलों में एक ही शासी नियम है: सर्टिओरारी केवल ए को रद्द करने के लिए उपलब्ध है कानून की त्रुटि के लिए निर्णय यदि त्रुटि रिकॉर्ड के चेहरे पर दिखाई देती है।”

डी.

इस प्रकार स्थिति का सारांश मॉरिस, एल. जे. द्वारा किया गया था। “यह स्पष्ट है कि प्रमाणपत्र छद्म रूप में अपील के लबादा के रूप में जारी नहीं किया जाएगा। यह कार्यवाही में उठाए गए मुद्दे की पुनः सुनवाई के लिए कोई आदेश या निर्णय लाने के लिए नहीं है। यह.

ई.

कानून की त्रुटि को ठीक करने के लिए मौजूद है जहां के चेहरे पर प्रकट किया गया है

एक आदेश या निर्णय, या अनियमितता, या अनुपस्थिति, या अधिकार क्षेत्र की अधिकता जहां दिखाया गया है।

वीरप्पा पिल्लई बनाम रमन एंड रमन लिमिटेड [(1952) एससीआर 583] में,

च

इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट गंभीर मामलों में जारी की जानी चाहिए जहां अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निकाय या अधिकारी पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना, या इससे अधिक कार्य करते हैं, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, या उनमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हैं, या इस पर एक स्पष्ट त्रुटि है

रिकॉर्ड का चेहरा "।टी. सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा [(1955)

जी.

एस. सी. आर. 250] कानून इस प्रकार कहा गया था: "निर्णय या निर्धारण में एक त्रुटि स्वयं 'सर्टिओरारी' के एक रिट के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन यह एक मैनिफेस्ट होना चाहिए

कार्यवाही के सामने स्पष्ट त्रुटि, उदाहरण के लिए, जब यह

ए के प्रावधानों की स्पष्ट अज्ञानता या उपेक्षा पर आधारित है

एच.

27

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन

मैथ्यू फिलिप और एनआर। ईटीसी। ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

कानून। दूसरे शब्दों में, यह एक पेटेंट त्रुटि है जिसे 'सर्टिओरारी' द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन केवल गलत निर्णय नहीं है।"

15. 2002 के अधिनियम 54 के पीछे का उद्देश्य और कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं।

जैसा कि इस न्यायालय ने मार्टिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम. संघ का

भारत, (2004) 4 एससीसी 311। हालाँकि यह न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप के बिना वसूली के एक तेज़ और सहज तरीके की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन यह न्यायाधिकरण के रूप में एक उचित तंत्र प्रदान करता है जिसे कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमाग द्वारा संचालित किया जाता है। न्यायाधिकरण के पास एक अवैध आदेश को दरकिनार करने और उसके बाद, फिर से कब्जा करने और मुआवजे और लागत के भुगतान सहित परिणामी राहत देने के लिए कई शक्तियां हैं। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 (1) "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति को एक विस्तृत अर्थ देती है, जो न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है।

ग

16. उधारकर्ता द्वारा एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना भी इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत है। मैडमस की रिट एक विशेषाधिकार प्राप्त रिट है। किसी कानूनी अधिकार के अभाव में, न्यायालय उक्त शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। वित्तीय लेन-देन में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब एक पक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आता है। जब कोई कानून किसी विशेष तरीके को निर्धारित करता है, तो दरकिनार करने के प्रयास को रिट अदालत द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। एक वादी न्यायाधिकरण से संपर्क करने के गैर-अनुपालन से बच नहीं सकता है जिसके लिए शुल्क के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है और एक विकल्प के रूप में संवैधानिक उपाय का उपयोग करता है। हम राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम एच. पी. राज्य, (2021) 6 एस. सी. सी. 771 में इस न्यायालय के हाल के फैसले को लाभ के साथ उद्धृत करना चाहते हैं।

डी.

ई.

“25. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के लिए "वैकल्पिक उपचार के नियम" और इसकी न्यायिक व्याख्या पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।

व्हर्लपूल कॉर्प में व्यापार चिह्न पंजीयक (1998) 8 एस. सी. सी.

च

1, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर मामले के कानून की समीक्षा करने के बाद कहा: (एस. सी. सी. पीपी. 9-10, पैरा 14-15)

“14. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और संविधान के किसी अन्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा न केवल संविधान के भाग III में निहित किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथास्थिति वारंट और प्रमाणपत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि "किसी अन्य उद्देश्य" के लिए भी किया जा सकता है।

जी.

एच.

28

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

15. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय आम तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन वैकल्पिक उपाय

इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वह कम से कम तीन आकस्मिकताओं में एक अवरोधक के रूप में कार्य नहीं करेगा, अर्थात्, जहां किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट याचिका दायर की गई है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या

ग

एक अधिनियम को चुनौती दी जाती है। इस बिंदु पर बहुत सारे मामले-कानून हैं लेकिन फॉरेंसिक बवंडर के इस चक्र को काटने के लिए, हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने फैसलों पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे अभी भी इस क्षेत्र में हैं।

(जोर दिया गया) 26। व्हर्लपूल कॉर्प में इस न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए।

डी.

ट्रेड मार्क्स के पंजीयक [(1998) 8 एस. सी. सी. 1], हरबंसलाल में

साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड [(2003) 2 एस. सी. सी. 107], इस न्यायालय ने नोट किया कि: (हरबंसलाल साहनिया मामला, एस. सी. सी. पृष्ठ 110, पैरा 7) "7. जहाँ तक उच्च न्यायालय का यह विचार है कि मध्यस्थता खंड का सहारा लेने के माध्यम से उपचार अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध था और इसलिए अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज होने के लिए उत्तरदायी थी, यह देखने के लिए पर्याप्त है कि एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के बहिष्करण का नियम विवेकाधिकार का नियम है और इनमें से एक नहीं है।

ई.

च

मजबूरी। एक उपयुक्त मामले में, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के बावजूद, उच्च न्यायालय अभी भी कम से कम तीन आकस्मिकताओं में अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है: (i) जहां रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग करती है; (ii) जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विफलता है; या (iii) जहां आदेश या कार्यवाहियां पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं या किसी अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी जाती है। (व्हर्लपूल Corpn.v देखें। व्यापार पंजीयक

जी.

मार्क्स [(1998) 8 एस. सी. सी. 1]। वर्तमान मामला पहली दो आकस्मिकताओं की प्रयोज्यता को आकर्षित करता है। इसके अलावा, जैसा कि उल्लेख किया गया है, अपीलार्थियों की डीलरशिप, जो उनकी रोटी और मक्खन है, ए.

एच.

29

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन

मैथ्यू फिलिप और एनआर। ईटीसी। ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

एक अप्रासंगिक और गैर-मौजूद कारण के लिए समाप्त किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में, हम महसूस करते हैं कि अपीलार्थियों को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता के बजाय स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा राहत दी जानी चाहिए थी।"

(जोर दिया गया) 27। कानून के जो सिद्धांत उभरते हैं वे हैं:

27.1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।

27.2. उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार नहीं करने का विवेकाधिकार है। उच्च न्यायालय की शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों में से एक वह है जहां पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

ग

27.3. वैकल्पिक उपचार के नियम के अपवाद उत्पन्न होते हैं जहाँ: (क) संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है; (ख) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है; (ग) आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना हैं; या (घ) किसी विधान के अधिकारों को चुनौती दी गई है।

डी.

27.4. एक वैकल्पिक उपाय अपने आप में उच्च न्यायालय को एक उपयुक्त मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों से वंचित नहीं करता है, हालांकि सामान्य रूप से, एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जब कानून द्वारा एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय प्रदान किया जाता है।

ई.

27.5. जब किसी कानून द्वारा कोई अधिकार बनाया जाता है, जो स्वयं अधिकार या दायित्व को लागू करने के लिए उपचार या प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपचार का आह्वान करने से पहले उस विशेष वैधानिक उपचार का सहारा लेना चाहिए। वैधानिक उपचारों के समाप्त होने का यह नियम नीति, सुविधा और विवेक का नियम है।

च

जी.

27.6. ऐसे मामलों में जहां तथ्य के विवादित प्रश्न हैं, उच्च न्यायालय एक रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है। हालांकि, यदि उच्च न्यायालय का निष्पक्ष रूप से यह विचार है कि विवाद की प्रकृति के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की आवश्यकता है, तो इस तरह के दृष्टिकोण में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।"

एच.

30

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

17. हम इस न्यायालय के पहले के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए सरफेसी अधिनियम से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप के संबंध में कानून की स्थिति को दोहराएंगे, जिसमें उच्च न्यायालयों से ऐसे मामलों पर विचार नहीं करने का अनुरोध करते हुए उक्त प्रथा की निंदा की गई है।

• फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस (2003) 10 एस. सी. सी. 733,

"18. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका (i) राज्य (सरकार); (ii) एक प्राधिकरण; (iii) एक वैधानिक निकाय; (iv) राज्य की एक साधन या एजेंसी; (v) एक कंपनी जो राज्य द्वारा वित्तपोषित और स्वामित्व में है; (vi) एक निजी निकाय जो काफी हद तक राज्य के वित्त पोषण पर चलता है; (vii) सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक प्रकृति के सकारात्मक दायित्व का निर्वहन करने वाला एक निजी निकाय; और (viii) किसी भी कानून के तहत किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए दायित्व के तहत एक व्यक्ति या निकाय के खिलाफ बनाए रखने योग्य हो सकती है।

ग

डी.

XXX XXX XXX

26. कंपनी अधिनियम के तहत किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से पंजीकृत कंपनी आजीविका कमाने और ऐसी गतिविधियों से लाभ कमाने के लिए एक निजी उद्यम है। बैंकिंग भी एक प्रकार का पेशा और एक व्यावसायिक गतिविधि है, इसके पीछे प्राथमिक उद्देश्य रिटर्न और लाभ अर्जित करना कहा जा सकता है। अनादिकाल से, ऐसी गतिविधियाँ आम तौर पर व्यक्तियों द्वारा की जाती रही हैं। यह कंपनी का एक निजी मामला है, हालांकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का मामला अलग है। ऐसी कंपनियाँ हो सकती हैं, जिनमें अधिकांश शेयर पूंजी का योगदान राज्य निधि से किया जा सकता है और इस मामले को देखते हुए कंपनी के मामलों के प्रबंधन में राज्य की अधिक भागीदारी या प्रमुख भागीदारी हो सकती है। लेकिन वर्तमान मामले में हम एक ऐसी बैंकिंग कंपनी के बारे में चिंतित हैं जिसके पास राज्य द्वारा किसी भी योगदान या हिस्सेदारी के बिना अपना धन जुटाने के लिए अपने संसाधन हैं। इसका अपना निदेशक मंडल है जिसे इसके शेयरधारकों द्वारा चुना जाता है। यह बैंकिंग व्यवसाय में किसी भी अन्य निजी कंपनी की तरह काम करता है जिसका कोई एकाधिकार नहीं है। कोई भी कंपनी ए

ई.

च

जी.

एच.

31

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन

पाँच लाख की पूंजी के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना एक अनुसूचित बैंक बन जाएगा। फिर भी, विभिन्न बैंकों द्वारा पूरी तरह से की जाने वाली बैंकिंग गतिविधि का निस्संदेह देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। शेयरधारकों और जमाकर्ताओं का पैसा ऐसी कंपनियों के पास होता है, जो बैंकिंग गतिविधि चलाती हैं। बैंक उधारकर्ताओं को किसी विशेष समय पर ब्याज की किसी भी दर पर वित्त प्रदान करते हैं। वे प्रतिभूतियों के बदले ऋण अग्रिम देते हैं। इसलिए, कंपनी, शेयरधारकों, जमाकर्ताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उचित वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के हित में ऐसी गतिविधियों पर नियामक जांच करना स्पष्ट रूप से आवश्यक है। राज्य की अर्थव्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य से बैंकिंग कंपनियों की स्थापना नहीं की गई है; दूसरी ओर ऐसी निजी कंपनियों को स्वेच्छा से उनके अपने उद्देश्यों और हितों के लिए स्थापित किया गया है, लेकिन उनकी गतिविधियों को नियंत्रण में रखा गया है ताकि उनकी गतिविधियाँ अनियंत्रित न हों और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचे। एक निजी बैंकिंग कंपनी जिसे पूरी स्वतंत्रता है, उसे इस तरह से कार्य करना पड़ता है कि वह राज्य की राजकोषीय नीतियों के साथ या उसके खिलाफ न हो और ऐसे उद्देश्यों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देश प्रदान किए जाते हैं ताकि अपने व्यवसाय को जारी रखने में अपने मामलों को संचालित करने के लिए एक उचित राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा जा सके। ताकि इस तरह के राजकोषीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो कभी-कभी कंपनी का प्रबंधन भी लिया जा सकता है। फिर भी, जैसा कि पहले देखा गया है, ये सभी नियंत्रण रखने और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए नियामक उपाय हैं, न कि कंपनी के मामलों पर सहभागी प्रभुत्व या नियंत्रण। सामान्य रूप से अन्य व्यावसायिक गतिविधियों, शायद विनिर्माण, अन्य उद्योगों या किसी भी व्यवसाय को करने वाली अन्य कंपनियों के लिए, इस तरह की जांच कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है। वहाँ भी, मुख्य विचार यह है कि कंपनी अपने स्वयं के कुप्रबंधन के कारण डूब नहीं सकती है या शेयरधारकों या लोगों के हितों को आम तौर पर उस कारण से खतरे में नहीं डाला जा सकता है। ऊपर बताए गए ऐसे हित का ध्यान रखने के अलावा, निजी कंपनियों के मामलों और प्रबंधन को नियंत्रित करने में राज्य का कोई अन्य हित नहीं है। कवर किए गए उद्योगों के संबंध में ध्यान रखा जाता है

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

32

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत कि उनका उत्पादन, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, कम न हो, फिर भी व्यावसायिक गतिविधि ऐसी कंपनियों या निगमों द्वारा की जाती है जो केवल उद्यमियों/कंपनियों की एक निजी गतिविधि बनी रहती है। 27. ऐसी निजी कंपनियाँ आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसे निजी निकायों या व्यक्तियों को एक रिट जारी की जा सकती है क्योंकि ऐसे कानून हो सकते हैं जिनका निजी कंपनियों सहित सभी संबंधितों द्वारा पालन करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कुछ कानून हैं जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाने अधिनियम या उचित पर्यावरण बनाए रखने के लिए, जैसे वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 या जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 आदि या समान प्रकृति के कानून जो ऐसे निजी निकायों पर कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को

वैधानिक रूप से निर्धारित करते हैं जिनका वे पालन करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे इस तरह के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से उन प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक रिट जारी की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई निजी नियोक्ता औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारी की सेवा प्रदान करता है, तो असंख्य मामलों में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है और उस संबंध में निजी निकायों और कंपनियों को रिट जारी करता है। लेकिन एक रिट जारी करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है जहां निजी निकाय द्वारा किसी भी वैधानिक प्रावधान का कोई गैर-अनुपालन या उल्लंघन नहीं हो सकता है। उस स्थिति में एक रिट बिल्कुल भी जारी नहीं की जा सकती है। अन्य उपचार, जो उपलब्ध हो सकते हैं, उनका सहारा लेना पड़ सकता है।"

ग

डी.

ई.

च

• यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन, (2010) 8

एस. सी. सी. 110 ", 42. There एक और कारण है कि विवादित आदेश को अलग रखा जाना चाहिए। यदि प्रतिवादी 1 को धारा 13 (4) के तहत जारी किए गए नोटिस या धारा 14 के तहत की गई कार्रवाई के खिलाफ कोई ठोस शिकायत थी, तो वह धारा 17 (1) के तहत आवेदन दायर करके उपचार का लाभ उठा सकती थी। धारा 17 (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति" व्यापक ए की है।

जी.

एच.

33

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन

मैथ्यू फिलिप और एएनआर। ईटीसी। ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

आयात करें। यह न केवल उधारकर्ता बल्कि गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति को भी अपने दायरे में लेता है जो धारा 13 (4) या धारा 14 के तहत की गई कार्रवाई से प्रभावित हो सकता है। न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों को धारा 17 और 18 के तहत अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार है और एक निश्चित समय अनुसूची के भीतर मामलों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरफेसी अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपचार त्वरित और प्रभावी दोनों हैं।

43. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य कानून की अनदेखी की कि यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी उपाय उपलब्ध है तो उच्च न्यायालय सामान्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार नहीं करेगा और यह नियम करेंगे, उपकर, शुल्क, अन्य प्रकार के सार्वजनिक धन और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बकाया की वसूली से जुड़े मामलों में अधिक सख्ती के साथ लागू होता है। हमारे विचार में, सार्वजनिक बकाया आदि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करते समय उच्च न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के बकाया की वसूली के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानून अपने लिए एक संहिता हैं क्योंकि उनमें न केवल बकाया की वसूली के लिए व्यापक प्रक्रिया शामिल है, बल्कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के निवारण के लिए अर्ध-न्यायिक निकायों के गठन की भी परिकल्पना की गई है। इसलिए, ऐसे सभी मामलों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर जोर देना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार का लाभ उठाने से पहले, एक व्यक्ति को संबंधित कानून के तहत उपलब्ध उपचारों का उपयोग करना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

44. उपरोक्त विचार व्यक्त करते हुए, हम इस बात से अवगत हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी करने की शक्तियां, जिनमें उचित मामले, कोई भी सरकार, निर्देश, आदेश या रिट शामिल हैं, जिसमें भाग III द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पांच विशेषाधिकार रिट शामिल हैं, बहुत व्यापक हैं और उस शक्ति के प्रयोग पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, लेकिन साथ ही, हम इस न्यायालय द्वारा विकसित किए गए स्व-लगाए गए प्रतिबंध के नियमों से अनजान नहीं हो सकते हैं, जो प्रत्येक उच्च न्यायालय है।

जी.

एच.

34

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखने के लिए बाध्य।

45. यह सच है कि वैकल्पिक उपचार के समाप्त होने का नियम विवेक का नियम है न कि मजबूरी का, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका पर विचार करना चाहिए और इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अंतरिम आदेश पारित करना चाहिए कि याचिकाकर्ता आवेदन, अपील, संशोधन आदि दायर करके प्रभावी वैकल्पिक उपचार का लाभ उठा सकता है और विशेष कानून में उसकी शिकायत के निवारण के लिए एक विस्तृत तंत्र शामिल है।XXX XXX XXX

ग

55. यह गंभीर चिंता का विषय है कि इस न्यायालय की बार-बार घोषणा के बावजूद, उच्च न्यायालय डी. आर. टी. अधिनियम और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत वैधानिक उपायों की उपलब्धता की अनदेखी करना जारी रखते हैं और उन आदेशों को पारित करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं जिनका बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के अपने बकाया की वसूली के अधिकार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।हम आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में अधिक सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ अपने विवेक का प्रयोग करेंगे।"

डी.

• स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम मैथ्यू के. सी. (2018) 3

ई.

एस. सी. सी. 85 ", 5. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है।आम तौर पर यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, न्यायालय की प्रक्रिया के प्रकट अन्याय या दुरुपयोग को रोकने के लिए।वर्तमान मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं।अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र निरपेक्ष नहीं है, लेकिन किसी मामले के दिए गए तथ्यों में और कानून के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।सामान्य नियम यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए यदि वैकल्पिक वैधानिक

उपचार उपलब्ध हैं, सिवाय उन मामलों के जो सी. आई. टी. बनाम छबील दास अग्रवाल [(2014) 1 एस. सी. सी. 603] में देखे गए अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों के भीतर आते हैं।(एस. सी. सी. पी. 611, पैरा 15)

च

जी.

एच.

35

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन

मैथ्यू फिलिप और एनआर। ईटीसी। ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

क.

“15. इस प्रकार, जबकि यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय ने वैकल्पिक उपचार के नियम के कुछ अपवादों को मान्यता दी है, अर्थात् जहां सांविधिक प्राधिकारी ने विचाराधीन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया है, या न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना की है, या उन प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया है जो निरस्त किए गए हैं, या जब कोई आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, तो थानसिंह नथमल बनाम अधीक्षक में निर्धारित प्रस्तावकों की धारा [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1419], टीटाघुर पेपर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य [(1983) 2 एससीसी 433:1983 एस. सी. सी. (कर) 131] और इसी तरह के अन्य निर्णय कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार नहीं करेगा यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है या जिस कानून के तहत शिकायत की गई कार्रवाई की गई है, उसमें शिकायत के निवारण के लिए एक तंत्र शामिल है। इसलिए, जब शिकायतों के निवारण के लिए कानून द्वारा एक वैधानिक मंच बनाया जाता है, तो वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।”

ग

डी.

XXX XXX XXX

ई.

8. एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि देश में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को दुनिया के वित्तीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों की तुलना में समान अवसर नहीं मिला। भारत में वित्तीय संस्थानों के पास प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने और उन्हें बेचने की शक्ति नहीं थी। वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचे ने बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ तालमेल नहीं रखा था, जिसके परिणामस्वरूप चूक करने वाले ऋणों की धीमी वसूली और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां हुईं। नरसिम्हन समिति I और II के साथ-साथ केंद्र सरकार अधिनियम द्वारा गठित अंधारुजिना समिति ने प्रतिभूतिकरण के लिए नए कानून बनाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और उन्हें अदालत के बिना बेचने के लिए सशक्त बनाने का सुझाव दिया था

च

जी.

एच.

36

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हस्तक्षेप जो उन्हें दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को प्राप्त करने, तरलता की समस्याओं का प्रबंधन करने, परिसंपत्ति देयता विसंगतियों और वसूली में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। समय के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (इसके बाद "डी. आर. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत कार्यवाही, त्वरित निर्णय को प्रभावित करने वाले नियमित न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही का पर्याय बन गई थी। विवादित आदेश पारित करने से पहले इन सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया है और उन पर विचार नहीं किया गया है।

9. एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम से पहले भी डी. आर. टी. अधिनियम के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपचार पर विचार करते हुए यह माना गया था

ग

पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओ. सी. कृष्णन (2001) 6 एस. सी. सी.

569] वह: (एस. सी. सी. पी. 570, पैरा 6) "6. यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करने की दृष्टि से लागू किया गया है। अधिनियम में अपील का एक पदानुक्रम प्रदान किया गया है, अर्थात् धारा 20 के तहत अपील दायर करना और इस त्वरित प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कार्यवाही का सहारा लेकर या दीवानी मुकदमा दायर करके पटरी से उतारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो स्पष्ट रूप से वर्जित है। भले ही किसी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से हटा नहीं सकता है, फिर भी, जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तो न्यायिक विवेक की मांग है कि न्यायालय उक्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से बचे। यह एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और प्रतिवादी को अधिनियम द्वारा प्रदान की गई अपील तंत्र का सहारा लेने का निर्देश देना चाहिए था।

डी.

ई.

च

जी.

XXX XXX XXX

15. यह न्यायालय का गंभीर कर्तव्य है कि वह किसी पक्ष द्वारा उठाई जाने वाली आपत्ति की प्रतीक्षा किए बिना सही कानून को लागू करे, विशेष रूप से जब कानून अच्छी तरह से तय हो। यदि अनुमत हो तो कोई भी प्रस्थान, मामले ए के चर्चा किए गए कारणों के लिए होना चाहिए।

एच.

37

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन

मैथ्यू फिलिप और एएनआर। ईटीसी। ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

एक परिभाषित अपवाद के तहत आने वाले, प्रासंगिक कानून को नोटिस करने के बाद विधिवत चर्चा की गई। वित्तीय मामलों में एकतरफा अंतरिम आदेशों के अनुदान का हानिकारक प्रभाव हो सकता है और यह कहना पर्याप्त नहीं है कि पीड़ित के पास अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए कदम उठाने का उपाय है। वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण करदाता के खर्च पर उत्पन्न

सार्वजनिक धन से दिए जाते हैं। इस तरह का ऋण ऋण लेने वाले व्यक्ति की संपत्ति नहीं बन जाता है, लेकिन जनता द्वारा प्रत्ययी क्षमता में दिए गए सार्वजनिक धन के अपने चरित्र को बरकरार रखता है। समय पर पुनर्भुगतान भी नकदी के संचलन द्वारा किसी अन्य जरूरतमंद को ऋण की सुविधा के लिए तरलता सुनिश्चित करता है और उन लोगों द्वारा तुच्छ मुकदमेबाजी द्वारा अवरुद्ध होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो उसी की विलासिता का खर्च उठा सकते हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन [(2010) 8 एस. सी. सी. 110 में व्यक्त सावधानी आवश्यक है: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 260], को भी विवादित अंतरिम आदेश पारित करने से पहले ध्यान में नहीं रखा गया है: (एस. सी. सी. पीपी. 123-24, पैरा 46)

ग

डी.

“46. यह याद रखना चाहिए कि करें, उपकर, शुल्क आदि की वसूली के लिए राज्य और/या उसकी एजेंसियों/उपकरणों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर रोक सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के निष्पादन में गंभीर रूप से बाधा डालती है और उन्हें नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक और कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने से अक्षम करती है। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सुरक्षित लेनदारों के बकाया की वसूली से संबंधित मामलों में, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक से ऐसे निकायों/संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो अंततः राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित होंगे। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में रोक लगाने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए। बेशक, अगर याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम है कि उसका मामला किसी भी अपवाद के दायरे में आता है

ई.

च

बाबूराम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम अंतरीम जिला परिषद [ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 556], व्हालपूल कॉर्पोरेशन। व्यापार चिह्न पंजीयक [(1998) 8 एस. सी. सी. 1] और हरबंसलाल साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन।

जी.

लिमिटेड [(2003) 2 एस. सी. सी. 107] और कुछ अन्य निर्णय, तो उच्च न्यायालय, सभी प्रासंगिक पर विचार करने के बाद

एच.

38

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

मापदंड और जनहित, एक उचित अंतरिम आदेश पारित करें।”

• फीनिक्स एआरसी (पी) लिमिटेड बनाम विश्व भारती विद्या

मंदिर, (2022) 5 एससीसी 345,

“18. अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निजी वित्तीय संस्थान-ए. आर. सी.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई/कार्रवाई के खिलाफ एक रिट याचिका को विचारणीय नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान मामले में, एआरसी ने एक सुरक्षित लेनदार के रूप में उधार ली गई राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा है। ए. आर. सी. को सार्वजनिक कार्य करने वाला नहीं कहा जा सकता है जो आम तौर पर राज्य अधिकारियों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है। वाणिज्यिक लेन-देन के दौरान और अनुबंध के तहत, बैंक/ए. आर. सी. ने इसमें उधारकर्ताओं को धन

उधार दिया और इसलिए बैंक/ए. आर. सी. की उक्त गतिविधि को सार्वजनिक कार्य करने के रूप में नहीं कहा जा सकता है जो आम तौर पर राज्य प्राधिकरणों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है। यदि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है और/या कोई प्रस्तावित कार्रवाई की जाती है और उधारकर्ता निजी बैंक/बैंक/ए. आर. सी. की किसी भी कार्रवाई से व्यथित है, तो उधारकर्ता को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठाना होगा और कोई रिट याचिका नहीं होगी और/या बनाए रखने योग्य और/या मनोरंजक होगी। इसलिए, प्रागा टूल्स कॉर्प में इस न्यायालय के निर्णय। बनाम सी. ए. इमान्युअल, [(1969) 1 एस. सी. सी. 585] और रमेश अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य, [(2012) 12 एस. सी. सी. 331; (2013) 3 एससीसी (एल एंड एस) 45; 4 एस. सी. ई. सी. 715] पर उधारकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा करना उधारकर्ताओं के लिए कोई सहायता नहीं है।

ग

डी.

ई.

च

XXX XXX XXX

जी.

21. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम मैथ्यू के. सी., [(2018) 3 एस. सी. सी. 85 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना: (2018) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 41] हाथ में तथ्यों के लिए, हमारी राय है कि संविधान ए के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उधारकर्ताओं द्वारा रिट याचिकाएं दायर करना।

एच.

39

मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस बनाम नवीन

मैथ्यू फिलिप और एएनआर। ईटीसी। ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

भारत सरकार अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है। धारा 13 (4) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह मानते हुए भी कि आई. डी. 1 का दिनांकित संचार धारा 13 (4) के तहत एक नोटिस था, उस मामले में भी, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील के माध्यम से उपलब्ध वैधानिक, प्रभावी उपचार को देखते हुए, उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा केवल 1 करोड़ रुपये (कुल 3 करोड़ रुपये) के भुगतान पर सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने वाला विवादित आदेश भी पूरी तरह से अनुचित है। बकाया राशि लगभग 117 करोड़ रुपये है। विज्ञापन अंतरिम राहत 2015 से जारी है और सुरक्षित लेनदार सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई से वंचित है। उच्च न्यायालय के समक्ष उधारकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर करना और कुछ नहीं बल्कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने शुरू में यांत्रिक रूप से और बिना कोई कारण बताए एक एकतरफा अंतरिम आदेश दिया है। उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि इस तरह का अंतरिम आदेश पारित करके, देय और देय राशि की वसूली के लिए सुरक्षित लेनदार के अधिकारों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। सुरक्षित लेनदार और/या उसके समनुदेशक को उधारकर्ताओं से देय और देय राशि की वसूली करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक का सुरक्षित लेनदार/समनुदेशक की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में रोक लगाते समय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए थी। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही खारिज किए जाने के योग्य है।"

ग

डी.

ई.

च

- वरिमडुगु ओबी रेड्डी बनाम बी. श्रीनिवासुलु,

जी.

(2023) 2 एस. सी. सी. 168 ", 36. तत्काल मामले में, हालांकि प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं ने शुरू में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत एक आवेदन दायर करके ऋण वसूली न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, लेकिन न्यायाधिकरण का आदेश

एच.

40

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

वास्तव में पूर्व-जमा की शर्त के अनुपालन के अधीन अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील योग्य था और अपील के वैधानिक उपचार को समाप्त किए बिना, प्रतिवादी उधारकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपचार को समाप्त किए बिना संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा रिट आवेदन पर विचार करने की इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिपथ मार्ग को 2002 के अधिनियम की धारा 18 के दूसरे प्रावधान के तहत पूर्व-जमा की शर्त से बचने के लिए अपनाया गया था।

ग

18. ऐसा करते समय, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियां काफी व्यापक हैं, लेकिन एक कानून के तहत कार्यवाही और न्यायनिर्णायक योजना से संबंधित मामलों में केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से एक ऋणदाता और एक उधारकर्ता से जुड़े वाणिज्यिक मामलों में, जब विधायिका ने उचित निवारण के लिए एक विशिष्ट तंत्र प्रदान किया है।

डी.

19. व्यक्त की गई चिंता को दोहराते हुए, वर्तमान अपीलों का निपटारा किया जाता है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति केरल उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को भेजे। खर्च की बाबत कोई आदेश नहीं।

ई.

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायक: राखी, एलसीआरए)

च

जी.

एच.